

अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों का भविष्य

साभार : बिजनेस लाइन

जोशुआ टी व्हाइट (सहायक प्रोफेसर, जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ

02 अगस्त, 2017

एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज, वॉशिंगटन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल ही में मोदी और ट्रम्प के बीच हुई बैठक कम वेग से उच्च जड़ता वाले संबंधों की ओर इशारा कर रही है जो एक स्वागत योग्य बदलाव का संकेत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जून में हुए शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और भारत दोनों के नीति विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। यात्रा का एक प्रमुख परिणाम अमेरिका-भारत रक्षा और सुरक्षा संबंधों में सुधार से संबंधित था।

क्या है खास -

1. रक्षा संबंधों की वृद्धि आश्चर्यजनक से कम कुछ नहीं है लगभग एक दशक के अंतराल में रक्षा व्यापार अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक का था।
2. अमेरिका और भारत कई और संयुक्त अभ्यासों में भाग लेंगे हैं और अमेरिका अब अपने सबसे करीबी सहयोगियों के अनुरूप एक संवेदनशील स्तर पर भारत के साथ संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के साझाकरण को अधिकृत करता है।
3. आतंकवाद सहयोग और खुफिया साझाकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ इस बार सुरक्षा साझेदारी को भी मजबूत किया गया है।

संयुक्त घोषणा पत्र-

1. ट्रम्प और मोदी द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य ने उपर्युक्त कथन को रेखांकित किया है और वास्तव में रक्षा सहयोग के लिए इस रणनीतिक तर्क को व्यापक बनाया है।
2. “सामान्य सिद्धांतों” जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य की सार्वभौमिकता के संबंध में एक समूह का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र-एशिया सहयोग के लिए अनिवार्यता की पुष्टि 2015 संयुक्त रणनीतिक विजन में की गयी है।
3. इसके अलावा इसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की भी अंतर्निहित आलोचना की गयी है जो साझा चिंताओं को दर्शाती है कि चीन श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे छोटे देशों की आजादी को सीमित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाएगा और उत्तर कोरिया, जो अपने पड़ोसी को नियंत्रित करने के लिए चीन के समान ही पैतरे अपना रहा है, पर सशक्त लगाम लगाना शामिल किया गया है।
4. अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदार (पिछले साल घोषित) के रूप में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ट्रम्प ने आगे के सहयोग के लिए कई अवसरों को उजागर कर दिया है।
5. जिसमें समुद्री डोमेन जागरूकता पर गहरा सहयोग और वार्षिक अमेरिका-भारत-जापान MALABAR अभ्यास पर निवेश शामिल है, जिसे ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से “विशाल हिंद महासागर में किए गए सबसे बड़े समुद्री व्यायाम” के रूप में वर्णित किया है और जिसमें एंटी-पनडुब्बी युद्ध पर अधिक ध्यान दिया गया है।
6. इस शिखर सम्मेलन में यह घोषणा कि गयी थी कि अमेरिका ने 22 सागर गार्जियन मानव रहित एरियल सिस्टम की बहु-अरब डॉलर की बिक्री की पेशकश की थी, जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के तहत “अस्वीकृति की अनुमानितता” पर काबू पाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता थी।
7. उनको खरीदना भारत के समुद्री निगरानी के लिए एक बरदान हो सकता है, लेकिन अन्य लंबी दूरी की अमेरिका की बिक्री के लिए दरवाजा भी खोल सकता है।

तीन क्षेत्रों में ध्यान देने कि आवश्यकता

1. सबसे पहले यह है कि हमे रक्षा बिक्री की स्थिर गति देखने को मिलेगी। भारत लंबे समय से रक्षात्मक आधुनिकीकरण के बीच फंसा हुआ है लेकिन नई दिल्ली की समझदारी ने अमेरिका-भारत रक्षा व्यापार के बढ़ते मांग को समझते हुए इस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया।
2. अमेरिका द्वारा कुछ संवेदनशील तकनीकों का प्रकाशन ऐतिहासिक रूप से सभी चार प्रमुख गैर-प्रसार शासनों में देश की सदस्यता पर किया गया है। भारत एमटीसीआर का सदस्य है, और अब वसीनर व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है, साथ ही वाशिंगटन चीन के समक्ष नई दिल्ली को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता के लिए तरफदारी कर रहा है।
3. तीसरा और अंतिम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है। मोदी और ट्रम्प दोनों ने सीमा सुरक्षा को बढ़ाने पर सहमती जताई है। यह स्पष्ट है कि भारत अमेरिका से 11 सितंबर, 2001 के बाद से अमेरिका द्वारा अपनी घरेलू सुरक्षा को बढ़ाए जाने के तरीके से एक बहुत कुछ सीख सकता है।
4. सीमा सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अमेरिकी तकनीकी सहायता को बढ़ाने के लिए खुफिया आदान-प्रदान करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जारी युद्ध को जीता जा सकता है।

- ट्रंप के अनुसार भारत 'ट्रेड बैरियर' को और शिथिल करे, ताकि अमेरिका अधिक निर्यात कर सके और अमेरिकी जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। तब बात समझ में आ गई कि यह राष्ट्रपति से अधिक एक कुशल व्यापारी है।
- यह देखने वाली बात थी कि ट्रंप को 'अमेरिका फर्स्ट' याद रहा, मगर मोदी 'मेक इन इंडिया' का नारा भूल गये। ट्रंप अपने चुनावी वायदे के प्रति गंभीर हैं, यह स्पष्ट दिख रहा था। दो अरब डॉलर की ड्रोन डील, अमेरिकी कंपनी लॉकलीड मार्टिन द्वारा 70 अरब डॉलर की सप्लाय और उसके रखरखाव व कलपुर्जा के लिए टाटा से समझौते को लेकर अमेरिका का उद्योग जगत खुश है।
- उससे पहले नागरिक विमानों की बड़ी खेप भारत में निर्यात किये जाने को उद्धृत करते हुए ट्रंप ने संदेश दिया कि इससे अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना को 200 अत्याधुनिक युद्धक विमानों की आवश्यकता है।
- इसके एक बड़े हिस्से का निर्यात अमेरिका करेगा, इसे ट्रंप की व्यापारिक सफलता के नुक्ते नजर से देखा जाना चाहिए। आगे ट्रंप यह चाह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, पेटेंट बीज, कृषि उपकरण, नाभिकीय ऊर्जा, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में जो नियामक बाधाएं हैं, भारत उसे सरल करे और 'फ्री एंड फेयर ट्रेड' का मार्ग प्रशस्त करे।
- ट्रंप ने जीएसटी को जल्द लागू किये जाने को जिस तरह से सराहा, इससे साफ था कि भारत में कर प्रणाली में हो रहे बदलाव पर अमेरिका की गहरी नजर है।
- इस यात्रा से पहले यह आशा थी कि मोदी 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। मगर, यह हुआ नहीं। एच1-बी वीजा पर चर्चा की उम्मीद 30 लाख अमेरिकन-इंडियन कर रहे थे।
- उनमें 700 से अधिक सिलिकॉन वैली की भारतीय कंपनियों को भरोसा था कि इसका रास्ता निकलेगा। मगर, इस विषय को सूची से बाहर रखा गया था। उसी तरह 'पेरिस पर्यावरण संधि' जैसे मुद्दे को मोदी ने दूर ही रखा। उलटा, ट्रंप ने कहा कि भारत से उभयपक्षीय व्यापार में घाटा हम उठा रहे हैं, उसे मोदी ठीक करें।
- अमेरिकी गृह मंत्रालय का एक महकमा है, 'ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म।' इस विभाग का काम है, दुनिया भर के दहशतगर्द संगठनों और उनके नेताओं को 'ग्लोबल टेररिस्ट' घोषित करना और जब वे दुरुस्त हो जाएं तो उनके नाम को सूची से बाहर कर देना। आतंकी सरगना हाफिज सईद अब इस सूची में 61वें नंबर पर हैं।
- चीनी हस्तक्षेप की वजह से यूएन में हाफिज सईद 'ग्लोबल आतंकी' घोषित नहीं हो सका। यह सच है कि पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से अमेरिका की सूची में 'ग्लोबल आतंकी' घोषित हो गया। मगर, ऐसा भी नहीं है कि इतना भर से हाफिज सईद को पाकिस्तान, भारत को सौंप देगा। चीन, एक बार फिर से हाफिज सईद की पीठ ठोक रहा है।
- चीन का सरल इलाज है, भारत उईगुर अलगाववादियों का समर्थन करे। इस शरारत के जनक नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने हिज्बुल आतंकी बुरहान वानी को संयुक्त राष्ट्र में दिये भाषण में 'कश्मीरी इंतफदा' का प्रतीक मान लिया था। आतंकी को समर्थन देने वाला भी आतंकी होता है, यह बात ट्रंप को समझाने की जरूरत है और पाकिस्तान को खैरात में करोड़ों डॉलर का खर्चा-पानी देने पर रोक लगाने के वास्ते माहौल बनाये रखना चाहिए।
- अमेरिकी गृह मंत्रालय के इसी 'ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म' ने 1997 में हरकतुल मुजाहिदीन, 2001 में जैश-ए-मोहम्मद व लश्करे तैयबा, 2003 में लश्करे झंगवी, 2010 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जुंदल्ला, 2012 में हक्कानी नेटवर्क, 2016 में भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय अल कायदा को 'ग्लोबल आतंकी संगठन' और इनके नेताओं को 'टेररिस्ट' घोषित किया था। 61 में से आठ 'ग्लोबल टेररिस्ट' पाकिस्तान में हैं। तो क्या अमेरिका ने उनका सफाया कर दिया? इसलिए हाफिज सईद के 'ग्लोबल टेररिस्ट' घोषित होने पर अति उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी उसे गुर्गा समेत जड़ से उखाड़ फेंकना है।
- फिर भी चीन की खुफिया एजेंसी 'एमएसएस' (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक््योरिटी), रूसी खुफिया 'एफएसबी' (फेडरल सिक््योरिटी सर्विस) और आईएसआई के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान ने अमेरिका को चिंता में डाल रखा है। इन तीनों एजेंसियों का दबाव अफगान खुफिया एजेंसी 'एनडीएस' पर है।
- 'एनडीएस' के बहुत सारे लोगों को भारतीय खुफिया एजेंसी 'रॉ' ने प्रशिक्षित कर रखा है, इस वजह से 'एनडीएस' से भारत की इंटेलेजेंस शेयरिंग अच्छे से हो जाती है। ट्रंप प्रशासन नये रणनीतिक गठजोड़ में भारतीय खुफिया एजेंसियों की बड़ी भूमिका चाहता है। कहीं ऐसा न हो, हमारा खुफिया तंत्र अमेरिकी हितों का साधन बन जाये।
- इस समय अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर जैसे कई मसलों पर एक दूसरे को असहज करते रहते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ सकते हैं। हो सकता है दोनों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ जाए। ट्रंप कई बार अपने भाषणों में चीन, जापान, मैक्सिको और यहां तक कि भारत पर भी अमेरिकी रोजगार छीनने का आरोप लगा चुके हैं। वे चीनी माल पर तगड़ा सीमा शुल्क (45 फीसदी तक) लगाना चाहते हैं और चीन के साथ व्यापार की शर्तों पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं।

संभावित प्रश्न

“भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सामरिक संबंध उनके 'साझा मूल्यों एवं हितों' तथा 'वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता' पर आधारित हैं। हालांकि भारत की इस कोशिश से चीन, पाकिस्तान और रूस की नाराजगी बढ़ सकती है।” इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)